कोटद्वार, शुक्रवार
13 फरवरी 2026
वर्षः 48
अंकः 260 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

डोली के आवगमन के लिए तैयारी शुरू

रुद्रप्रयाग। अगस्त्य मुनि महाराज की पावन डोली एक महीने की यात्रा के बाद अपने सैण (मैदान) की ओर प्रस्थान करने जा रही है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को अगस्त्य पंचकोटी संघर्ष समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष राजेश बेंजवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराज की डोली क्षेत्रीय भ्रमण कर गद्दीस्थल की ओर प्रस्थान कर रही है। कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से सामूहिक सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

इस दौरान शेखर नौटियाल, सुशील गोस्वामी, गजपाल सिंह, गंगू कोठियाल, मनवर सिंह रावत, दीपक बेंजवाल, उत्तम नेगी, अर्जुन सिंह नेगी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए सामूहिक सहयोग का संकल्प लिया।

करोड़ों की सरकारी संपति बनी खंडहर

उत्तरकाशी। नेताला में अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय बना अचल प्रशिक्षण केंद्र और कोविड महामारी के समय करोड़ों की धनराशि खर्च कर बना आरपीसीआर लैब का भवन जर्जर बना है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और शासन–प्रशासन की अनदेखी के कारण सरकारी संपदा बरबाद हो रही है। केंद्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्र के एएनएम को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। वहीं आरपीसीआर लैब के भवन में उच्च तकनीकी लैब स्थापित की जानी थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपनी संपत्ति की स्थिति का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

नेताला में अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय अचल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण इसलिए किया गया था कि सीमांत जनपद के युवाओं को अपने घर पर भी एएनएम का प्रशिक्षण मिल पाएगा लेकिन इसके भवन का कभी प्रयोग नहीं किया गया। उत्तराखंड बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद यह केंद्र शुरू होने से युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षण मिलेगा लेकिन सरकारें बदली और समय के साथ इसका बहुमंजिला भवन जर्जर होने के कारण वीरान हो गया। कोविड महामारी के दौरान आरपीसीआर जैसी जांचों के लिए लोगों को देहरादून की दौड़ लगानी पड़ रही थी तो उस समय शासन–प्रशासन ने वहां पर केंद्र के नजदीक में खाली पड़ी भूमि पर करोड़ों की लागत से लैब भवन का निर्माण किया गया। अब दोनों भवनों का प्रयोग नहीं होने के कारण ग्रामीणों के घास और अन्य सामान रखने के काम में प्रयोग हो रहा है लेकिन शासन–प्रशासन की ओर से इन भवनों के उचित प्रयोग के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सीएमओ डॉ. बीएस रावत का कहना है कि केंद्र के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। दो से तीन माह में इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद है।

पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें 'डबल, अब बेटे रनिंदर को ईडी ने भेजा समन

जालंधर ,पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (स्नश्वरू) के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने पिता–पुत्र को विदेशी संपत्तियों के मालिकाना हक और कथित अवैध लेनदेन के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज, गुरुवार (12 फरवरी 2026) को अपने जालंधर स्थित आंचलिक कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया था, जबकि उनके बेटे रनिंदर सिंह को कल यानी शुक्रवार (13 फरवरी 2026) को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

अस्पताल में भर्ती हैं कैप्टन, मिलेगी नई तारीख

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें हाल ही में मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस वजह से वे जालंधर नहीं आ सकते।

माना जा रहा है कि उनकी लीगल टीम ईडी को उनकी मेडिकल स्थिति की जानकारी देगी, जिसके बाद एजेंसी उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोई नई तारीख दे सकती है।

अर्जुन हत्याकांड का खुलासाः

प्रॉपर्टी के विवाद में मां ने ही कराई बेटे की हत्या

12 लाख में दी थी सुपारी

देहरादून में बुधवार को तिब्बती मार्केट के सामने कारोबारी और टेनिस प्लेयर अर्जुन की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेसवार्ता कर बताया कि बलिदानी कोटे से परिवार को मिली गैस एजेंसी के लोन चुनाने को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके बाद मृतक की मां बीना शर्मा ने ही बेटे अर्जुन की हत्या करवाई थी। उन्होंने बताया कि मां ने शूटरों को 12 लाख रुपये में सुपारी दी थी। जिसमें से तीन लाख रुपये दे दीए थे। बाकी रकम काम होने के बाद देनी थी।

25 दिन पहले ही दे दी थी सुपारी

एसएसपी ने बताया कि मां बीना ने 25 दिन पहले ही बेटे की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। मां बीना शर्मा शातिर अपराधियों की तरह बेटे की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उसने गैस एजेंसी के मैनेजर से अर्जुन की मूवमेंट की जानकारी भी ली थी।

आठ करोड़ रुपये बने हत्या की असली वजह

बताय कि बीते दिनों बीना ने जीएमएस रोड की प्रॉपर्टी बेची थी। जिसे बेचने के बाद 14 करोड़ रुपये बीना के खाते में आए थे। इसमें से आठ करोड़ रुपये उसने विनोद के खाते में भेजे थे। इसके बाद जब अर्जुन ने इसका विरोध किया तो मां ने हत्या की साजिश रची थी।

हत्याकांड के बाद पुलिस ने शूटर और उसके सहयोगी को अलग–अलग स्थानों पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। हत्याकांड के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए शहर से लेकर देहात तक नाकेबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अब 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली , चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सोमवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव के 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि चुकाने के आश्वासन पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मामला काफी समय से लंबित है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने बताया कि पुनरीक्षण सुनवाई और मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कई बार वादे किए जाने के बावजूद, राजपाल यादव ने लगभग 25–30 बार सुनवाई स्थगित करवाई और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा, 'आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। कोर्ट का कहना है कि राजपाल यादव को कम से कम दो दर्जन से ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजपाल यादव ने परिवार में शादी का हवाला देते हुए बेल मांगी थी। बार एंड बेंच के अनुसार, सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें आपके प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। आपने अदालत के आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं किया और तभी आत्मसमर्पण किया जब अदालत ने दोबारा आदेश जारी किया।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक, परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत मंथन

–विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख, वितरण लॉस व विद्युत चोरी पर जीरो टॉलरेंस

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गत वर्षों में पूर्ण की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की उपलब्धियों, एडीबी पोषित एवं नॉन–एडीबी पोषित गतिमान परियोजनाओं, मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं, मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित कार्यों तथा आरईसी/पीएफसी पोषित योजनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही वर्ष 2025–26 में अतिरिक्त अंश पूंजी (राज्य सेक्टर एवं रअरउक), प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्षवार अंश पूंजी की आवश्यकता, पिटकुल के रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान/मास्टर प्लान, आपदा मद में क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि एवं मानव शक्ति की

आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशः समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

मुख्यमंत्री ने विद्युत वितरण लॉस को न्यूनतम करने, विद्युत चोरी पर सख्ती से रोक लगाने तथा वितरण लॉस में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन को देखते हुए यूजेवीएनएल, पिटकुल एवं यूपीसीएल को अभी से समस्त तैयारियां सुनिश्चित करने, सभी औपचारिकताओं को मार्च तक पूर्ण कर अप्रैल तक परियोजनाओं के शुभारंभ हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

सीएसआर मद में प्राप्त धनराशि के लिए पृथक खाता खोलकर उसका अधिकतम एवं बहु–रचनात्मक उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया। विभिन्न जनपदों में एडीबी पोषित उपकेंद्रों से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। एडीबी पोषित द्वितीय चरण के अंतर्गत बहादराबाद (हरिद्वार), कोटद्वार (पौड़ी), भिकियासैंण (अल्मोड़ा), कपकोट (बागेश्वर) एवं नंदप्रयाग (चमोली) में भूमि आवंटन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत शिलान्यास की गई सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से पूर्ण करने हेतु निरंतर निगरानी एवं प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

पिटकुल की उल्लेखनीय उपलब्धियां और वित्तीय सुदृढ़ता

पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी सी. ध्यानी ने विगत चार वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि आरईसी द्वारा पिटकुल की क्रेडिट रेटिंग किए जाने से परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्राप्त ऋणों पर 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को कम टैरिफ के रूप में प्राप्त होगा।

शारदीय कांवड़ यात्रा में बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़

हरिद्वार। महाशिवरात्रि पर्व नजदीक आते ही शारदीय कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु हरकी पैड़ी सहित विभिन्न घाटों से कांवड़ में गंगाजल भरकर गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। महाशिवरात्रि तक लाखों शिवभक्तों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इससे मेला क्षेत्र में रौनक और आस्था का माहौल गहराता जा रहा है। अगले तीन दिन हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भीड़ रहेगी।। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, वहीं यातायात संचालन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। हरकी पैड़ी, प्रमुख घाटों और बाजारों में चौकसी बढ़ाई गई है तथा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में चारों ओर बोल बम और हर–

हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। शारदीय कांवड़ यात्रा में इस बार भी पैदल कांवड़ियों की संख्या अधिक देखी जा रही है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सहित विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से भी श्रद्धालु गंगाजल लेने आ रहे हैं। कांवड़िये कई दिनों तक पैदल यात्रा कर महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने क्षेत्र के शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। धर्मनगरी में बढ़ती भीड़ के साथ आस्था और उत्साह का रंग और गहरा होता जा रहा है।

खरसिया कार्बन प्लांट ब्लास्टः पिता–पुत्र और 9 माह की मासूम समेत चार की मौत

रायगढ़ ,खरसिया के मंगल कार्बन प्लांट में हुए भीषण विस्फोट ने एक ही परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। इस दर्दनाक हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान 9 माह की मासूम बच्ची के बाद 11 फरवरी को तीन अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में पिता, पुत्र और मासूम बच्ची शामिल हैं, जिससे परिवार पर असहनीय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक के लिए ?12,12 लाख मुआवजे की घोषणा की है, जो अपर्याप्त है। उनका कहना है कि प्रत्येक मृतक के बदले कम से कम ?50झ50 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और उचित पुनर्वास पैकेज दिया जाए।

लड़कियों की शादी पर सरकार देगी एक लाख रुपए : सीएम योगी

लखनऊ ,उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख (9,12,696.35 करोड़ रुपए) का बजट पेश किया। इस बजट में 43,565.33 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित हैं।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। तकनीक आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 'नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य में डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये देगी। यूपी का इस बार का बजट का आकार नौ लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का है।

पिछले बजट की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। सुरेश खन्ना ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने के लिए एआई मिशन और 'टेक युवा समर्थ युवा योजनाझ् शुरू की जाएगी, जिसके जरिए युवाओं को उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। ऊर्जा क्षेत्र में डीजल आधारित नलकूपों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा आधारित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाकर युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा।

उन्होंने सदन को जानकारी दी कि उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रदेश देश में अग्रणी स्थिति में है। उन्होंने बताया कि गेहूं और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है और निवेश का प्रवाह तेज हुआ है। औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से आर्थिक परिदृश्य मजबूत हुआ है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

राज्यसभा में बोले खड़गे, सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं, संविधान की आत्मा है

नई दिल्ली ,। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम अक्सर दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करते हैं। अब समय है कि इन बातों को जमीन पर उतारने की ठोस पहल की जाए। सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इक्कीसवीं सदी में, जब हम सामाजिक विकास, सुधार और एकता की बातें करते हैं, तब ओडिशा की एक घटना हमें आईना दिखाती है। वहां एक आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ इसलिए तीन महीनों से बहिष्कार चल रहा है क्योंकि भोजन एक दलित महिला हेल्पर और कुक द्वारा तैयार किया जा रहा है। समुदाय विशेष के कुछ लोग अपने बच्चों को वह भोजन देने से

मना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की भी परीक्षा है। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद गंभीर विषय है, जिस पर वह सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की बुनियाद होते हैं। अगर वहां जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी जाएगी, तो उसका सीधा असर बच्चों के मन और उनके भविष्य पर पड़ेगा। छोटे–छोटे बच्चों के सामने जब इस तरह का भेदभाव होता है, तो अनजाने में उनके भीतर भी विभाजन और नफरत के बीज बो दिए जाते हैं। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत शिक्षा के अधिकार की भावना को कमजोर करती है। साथ ही, अनुच्छेद 47 के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह पोषण स्तर को बढ़ाए और जनस्वास्थ्य में सुधार करे। अगर पोषण कार्यक्रम ही जातिगत सोच की भेंट चढ़ जाएं, तो यह राज्य के दायित्व पर भी सवाल खड़ा करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस घटना को केवल एक सामाजिक विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसे कार्यस्थलों पर होने वाले व्यापक जाति–आधारित भेदभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं।

राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव प्रतिबंध की मांग

नई दिल्ली ,। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। बुधवार (11 फरवरी) को राहुल गांधी ने सदन में सरकार पर भारत माता को बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव (मोशन) पेश करने की बात कही है। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने अपने प्रस्ताव में इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग भी उठाई है। निशिकांत दुबे ने बयान में कहा कि उनका आरोप है कि राहुल गांधी कथित तौर पर बाहरी ताकतों की मदद से देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस कदम से संसद में सियासी माहौल और गर्म हो गया है। वहीं, कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत–अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे किसानों को भारी नुकसान होगा।

लोकसभा स्पीकर के चैंबर में जबरन घुसे कांग्रेस सांसद, गाली गलौच की

नई दिल्ली ,। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई सांसदों ने जबरन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में घुसकर उन्हें गालियां दीं और धमकाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने बयान में कहा, कांग्रेस के 20–25 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में जबरदस्ती घुसे। वहां उनकी तरफ से गाली गलौच की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस सांसदों ने गालियां दीं। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैंबर में ही कांग्रेस के सांसदों ने धमकी दी थी कि जब सदन में बोलने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद के अंदर की घटना सभी ने देखी और वह रिकॉर्ड भी हुई।

कानून व्यवस्था ध्वस्त, पेपर लीक और महंगाई से त्रस्त है जनता : हरक

देहरादून। 6 फरवरी को होने वाली कांग्रेस की उत्तराखंड बचाओ भाजपा भगाओ रैली और राजभवन घेराव की तैयारियां तेज हो गई है। गुरुवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र के इंद्रानगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में न महिलाएं सुरक्षित हैं, न किसान खुशहाल हैं और नौजवान बेरोजगारी से हताश है। डॉ. रावत ने अंकिता भंडारी केस में सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार का रवैया संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल माफिया ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कि कैंट क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता रैली में परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जनता नौ साल में भ्रष्टाचार और महंगाई से अजीज आ चुकी है। वहीं, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने दून में 14 दिन में हुई चार हत्याओं का हवाला देकर कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया।

'हम लेंगे एक्शन', पीएम मोदी के राजनीतिक करियर पर ट्रंप का बयान

भारत ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एक पुराने बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय (टएअ) की प्रतिक्रिया सामने आई है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर से जुड़ा था, जो पिछले साल अक्टूबर में दिया गया था। अब यह वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ट्रंप के इस बयान के बारे में सवाल

पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, "मैंने वीडियो नहीं देखा है। हालांकि अगर ऐसा कोई वीडियो है, चाहे वह सही हो या गलत, हम उस पर सही एक्शन लेंगे।"

यह बयान ट्रंप ने 15 अक्टूबर 2025 को दिया था। उस समय भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्तों में कुछ तनाव था।

ट्रंप ने क्या कहा था?

व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने मोदी को 'महान व्यक्ति' और मजबूत नेता बताया था। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। हालांकि, भारत ने ऐसे किसी पक्के भरोसे से इनकार किया था। भारत का साफ कहना रहा है कि उसके लिए 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वह अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर फैसले लेता है।

ऋषिकुल कश्यप घाट के पास पार्क में झूले से लटका मिला शव

हरिद्वार। शहर के ऋषिकुल कश्यप घाट के सामने स्थित पार्क में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव झूले से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह गीता पत्नी स्व. सुशील निवासी ऋषिकुल कश्यप घाट ने पुलिस को सूचना दी कि पार्क में एक व्यक्ति का शव झूले से लटका हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। तलाशी लेने पर मृतक के पास पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। मृतक की जेब से 10 फरवरी का दिल्ली से हरिद्वार आने वाली रोडवेज बस का टिकट बरामद हुआ है।

बूंदी में भीषण सड़क हादसा : बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को रौंदा

एक ही परिवार के तीन मासूमों की मौत, पिता की हालत नाजुक

बूंदी , कोटा–भीलवाड़ा नेशनल हाईवे–27 पर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। डाबी थाना क्षेत्र के दुधी कुड़ी कट पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो सगे भाई–बहन और उनके एक चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चों के पिता गंभीर रूप से घायल हैं। बीमार बच्चे को दवा दिलाने जा रहे थे, रास्ते में मिली मौत पुलिस के अनुसार, पराणा गांव निवासी मदन बंजारा अपनी बेटी सुमन, बेटे अंकित और भतीजे करण को लेकर बाइक से डाबी की ओर जा

रहे थे। परिवार के एक बच्चे की तबीयत खराब थी और मदन उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वे नेशनल हाईवे–27 पर दुधी कुड़ी कट के पास पहुंचे, बिजौलिया की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

रूह कंपा देने वाला मंजर : दूर तक घिसटते गए मासूम

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रेलर बाइक को काफी दूर तक घसीटता ले गया। मासूमों की मौत : 8 से 10 साल की उम्र के तीनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पिता की स्थिति : मदन बंजारा लहूलुहान हालत में सड़क पर मिले, जिन्हें तत्काल कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

सम्पादकीय

मां का रिश्ता कलंकित

रिश्तों की अगर बात हो तो "मां" एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। मां का स्थान सभी रिश्तों से ही नहीं, बल्कि भगवान से भी ऊपर रखा गया है। ऐसे कितने ही उदाहरण है जिनमें अपने बच्चों के लिए मां अपना तन मन धन तक बलिदान करने से पीछे नहीं हटती लेकिन अब वक्त कलयुग का आ गया है तो रिश्तो का वह स्वरूप भी देखने को मिलेगा जिसकी शायद उम्मीद ही ना की जाती हो। जब एक मां के कारनामे ही जघन्य अपराधों के तौर पर सामने आएंगे तो रिश्तों की मर्यादाएं एवं सीमाओं के टूटने पर समाज अचंभित तो होगा ही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गैस एजेंसी के मलिक को दो लोगों ने सड़क पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो रिश्तों का ऐसा काला काला चेहरा सामने आया जिसने इस पवित्र रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए। संपत्ति के लेनदेन को लेकर मां और बेटे के बीच विवाद चला आ रहा था जिसमें पहले मां ने अपने ही बेटे से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा ले रखी थी। हालांकि इसके बाद भी संपत्ति का विवाद सुलझा नहीं पाया और करोड़ों की देनदारी मां के ऊपर बन गई जिसके एवज में मां अपने बेटे द्वारा लगाए गए प्रॉपर्टी पर स्टे को लेकर उसकी मौत की साजिश बना बैठी। मां ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर अपने ही बेटे के हत्या का षड्यंत्र बना और12 लाख रुपए में सौदा तय करते हुए रिश्तों में अंतिम कील ठोक दी। हालांकि पुलिस जांच में पहले ही यह सब सामने आ चुका था और जल्द ही पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर समेत हत्यारे एवं कलयुग की इस मां को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने समाज के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है की क्या मां और बेटे जैसे सबसे गहरे संबंधों में वह स्थिति भी आ सकती है जिसमें एक मां अपने ही बेटे को मरवाने के लिए लाखों रुपए की सौदेबाजी कर बैठे। शायद इसे ही कलयुग की शुरुआत कहते हैं जहां रिश्तों की कोई मायने नहीं रह जाएंगे और सब कुछ भौतिकवाद के इर्द–गिर्द ही मंडराता हुआ नजर आएगा। रिश्ते महज दिखावे के होंगे या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जहां अपनों की ही जान लेने के लिए भी इंसान किसी भी हद तक जाएगा।

अब कमंडल ही मंडल हो गया

पहले कानून के हिसाब से देखें तो भारत में माना जाता है कि हर अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। लोग उसमें लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब कानून ही खराब हो तो क्या होगा? तब तो उस कानून के दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। फिर तो उसके सदुपयोग से भी लोगों को फंसाया जा सकता है या किसी को बचाया जा सकता है। यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए थे वो नियम इस दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे इतने खराब हैं कि उनके दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। उनके सदुपयोग से भी देश के एक छोटे से जातीय समूह के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है और उनके करियर पर ग्रहण लगाया जा सकता है।

हरिशंकर व्यास

यह सवाल इसलिए है क्योंकि भाजपा सरकार ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से ऐसा नया नियम जारी कराया, जिससे देश के करीब ढाई हजार उच्च शिक्षा संस्थानों की तस्वीर बदल जाती। यह कहना अतिरंजित लग सकता है लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यूजीसी के नियम उसी रूप में लागू होते, जिस रूप में उनको जारी किया गया था तो देश के उच्च शिक्षण संस्थान नब्बे के दशक का बिहार और उत्तर प्रदेश बन सकते थे। लालू यादव की पार्टी की एक प्रवक्ता ने इसका इशारा भी किया था। जब इन नियमों के हवाले उससे पूछा गया कि इसके जरिए तो अगड़ी जाति के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है तो उसने दो टूक अंदाज में कहा कि इनको फंसाया जाना चाहिए क्योंकि ये 90 फीसदी बहुजन के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसने हजारों साल के दमन, अत्याचार वगैरह की बातें भी कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई तो सुनवाई के दौरान लालू यादव की पार्टी की प्रवक्ता के उस बयान का भी जिक्रएक वकील ने किया था।

पहले कानून के हिसाब से देखें तो भारत में माना जाता है कि हर अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। लोग उसमें लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब कानून ही खराब हो तो क्या होगा? तब तो उस कानून के दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। फिर तो उसके सदुपयोग से भी लोगों को फंसाया जा सकता है या किसी को बचाया जा सकता है। यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए थे वो नियम इस दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे इतने खराब हैं कि उनके दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। उनके सदुपयोग से भी देश के एक छोटे से जातीय समूह के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है और उनके करियर पर ग्रहण लगाया जा सकता है।

ध्यान रहे शिक्षण संस्थानों में किसी तरह का भेदभाव रोकने के नियम पहले से बने थे। यूपीए सरकार के समय यूजीसी ने 2012 में नियम बनाए थे, जिनमें सभी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के प्रावधान किए गए थे। लेकिन 2026 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय जो नियम जारी किए गए उसमें कई चीजें बदल दी गईं। पहले नियम में सिर्फ भेदभाव की बात कही गई थी, जबकि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की बात जोड़ दी गई और सामान्य वर्ग को छोड़ कर बाकी सबको भेदभाव के संभावित शिकार के तौर पर परिभाषित किया गया। इसी तरह पुराने नियम में गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया।

इस तरह गलत शिकायत करके किसी को फंसाने का लाइसेंस दिया गया। पुराने नियम में शिकायत सुनने वाली कमेटी में सभी वर्गों के सदस्य रखने का प्रावधान था, जबकि नए नियम में एससी, एसटी, ओबीसी सदस्य रखने को अनिवार्य किया गया और सामान्य वर्ग का सदस्य रखने की अनिवार्यता नहीं रखी गई। नए नियम में भी रैगिंग को शामिल नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर रैगिंग का शिकार सामान्य वर्ग का कोई लड़का शिकायत करे तो क्या उसके ऊपर भी भेदभाव की कार्रवाई हो सकती है।सवाल है कि क्या यूजीसी ने बिना सोचे समझे ये नियम जारी कर दिए या कोई ऐसा बैठा है, जिसके मन में सामान्य वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह है और उसने सबक सिखाने के लिए इस तरह के नियम बनाए या सोच समझ कर राजनीतिक योजना के तौर पर ये नियम बनाए गए ताकि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के हाथ से बहुजन राजनीति का कार्ड छीना जा सके? ध्यान रहे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बहुत सावधान हो गई है। उससे पहले भाजपा अपने को अजेय मान रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस या उसके नेतृत्व में एकजुट विपक्ष भी कभी उसको नहीं हरा पाएगा। लेकिन संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, जाति गणना कराओ आदि के नारे पर विपक्ष ने भाजपा की हवा निकाल दिया। लोकसभा चुनाव में चार सौ सीट हासिल करने के लक्ष्य को पंक्चर किया। 'जितनी आबादी उतना हकइ का राहुल गांधी का नारा हिट हुआ। तभी पिछड़ा, दलित और आदिवासी की ओर ध्यान गया। पहले नरेंद्र मोदी जिस तरह 'मुफ्त की रेवड़ीइ से घबराए उसी तरह जाति वाले दांव से घबराए हुए हैं।

ध्यान रहे नरेंद्र मोदी ने ही 'मुफ्त की रेवड़ीइ का जुमला बोला था।

उन्होंने कहा था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। लेकिन जब लगा कि 'मुफ्त की रेवड़ीइ का दांव विपक्ष के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस कर्नाटक जीत गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं हार रहे हैं। तो उन्होंने भी सबको खजाना खोलने की इजाजत दी। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को देश भर में भाजपा ने भी आजमाया। उसी तरह बिहार में जाति गणना हुई और राहुल ने कर्नाटक, तेलंगाना में इसकी घोषणा की तो प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़ कर जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। अगले साल जनगणना होगी, जिसमें 1931 के बाद पहली बार देश भर की जातियों की गिनती होगी। तो क्या अब बाजी पलट गई है? अब विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और भाजपा व उसकी सरकार उस पर प्रतिक्रिया दे रही है?

ऐसा लग रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के नाम पर जो नियम घोषित किए गए थे वो जाति गणना से आने वाले आंकड़ों को ध्यान में रख कर किए गए थे। पहले से ही सरकार और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। बहुजन को साधने का प्रयास चल रहा है। उनको मैसेज दिया जा रहा है कि देखो भाजपा और नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए अपने सबसे मजबूत सवर्ण समर्थकों को भी नाराज करने का जोखिम लेने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद में जिस तरह के प्रदर्शन हुए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर लोगों ने जूते चलाए और आग लगाई, मोदी–योगी मुर्दाबाद के नारे लगे उन तस्वीरों ने निश्चित रूप से पिछड़े, दलितों में मोदी के प्रति सहानुभूति जगाई होगी।

आगे पता नहीं क्या होगा लेकिन अगड़ी जातियों ने जिस तरह का उबाल दिखाया और जितनी हिंसक प्रतिक्रिया दी उसका राजनीतिक असर निश्चित रूप से हुआ होगा। मन ही मन पिछडी जातियों ने गांठ बांधी होगी। यह भी ध्यान रखने की बात है कि भाजपा के किसी नेता ने इस नियम के खिलाफ बयान नहीं दिया। कई सवर्ण नेता भी इसे डिफेंड करते रहे। यह अहसान बताते रहे कि मोदी ने अगड़ी जातियों को ईडब्लुएस के तहत 10 फीसदी आरक्षण दिया है। तभी सवाल है कि व्यापक हिंदू समाज की एकता बनाने की बात करने वाली भाजपा और आरएसएस की यह कैसी सोच है? एक तरह 'बंटोगे तो कटोगेइ के नारे हैं और दूसरी ओर हिंदू समाज को ही अगड़ा और पिछड़ा में बांटने की राजनीति हो रही है। यही काम तो नब्बे के दशक में वीपी सिंह करके गए थे। तब भी अगड़ी जातियों ने ऐसे ही प्रदर्शन किए थे, जिसका लाभ आज तक मंडल की पार्टियों को मिल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी मंडल की पार्टियों से उनका राजनीतिक दांव छीन रहे हैं? हो सकता है क्योंकि उनके समर्थक भी कहते हैं कि उन्होंने मंडल और कमंडल को मिला दिया है। वाजपेयी, आडवाणी, जोशी के समय दोनों अलग थे लेकिन अब कमंडल ही मंडल हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है अगड़ी जाति के अपने वोकल समर्थकों को नाराज कर भाजपा पहले से विभाजित पिछड़े, दलित और आदिवासी वोट के सहारे चुनाव जीत पाएगी? ध्यान रहे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने पहले ही 15 फीसदी मुसलमानों, करीब चार फीसदी ईसाई और दो फीसदी सिख यानी 21 फीसदी अल्पसंख्यकों को अपने से अलग कर दिया है। अब 15 फीसदी ही सही लेकिन अगड़े भी अलग होते हैं या उनका मोहभंग होता है तो क्या भाजपा को इसका नुकसान नहीं होगा?

हड़ताल श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती है

एस. पी. तिवारी

चार नयी श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, भारत की विशाल श्रम शक्ति, विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जीवन यापन में आसानी में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों का उद्देश्य, बिना जटिल उद्योग वर्गीकरण की बाधाओं के, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देना है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अनिवार्य पहचान पत्र की शुरुआत करते हुए, ये संहिताएं उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीधी पहुंच की सुविधा के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। नियमित और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, श्रमिकों की भलाई में मदद करेंगी, जिससे वे स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा, समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था, पीड़ित श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक तनाव और अनिश्चितता को कम करने में सहायता करेगी। समग्र रूप से, ये उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित एक प्रगतिशील रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, इन सकारात्मक प्रावधानों के बावजूद, राजनीतिक रूप से प्रेरित केंद्रीय श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) का एक हिस्सा अक्सर हड़ताल के प्रतिकूल प्रभाव पर पूरी तरह विचार किए बिना, हड़ताल पर उतर आता है। ऐसी हड़तालों से विशेष रूप से असंगठित अर्थव्यवस्था के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के पारिश्रमिक को भारी नुकसान होता है, जो अपनी जीविका के लिए दैनिक आय पर निर्भर होते हैं। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय, बार–बार होने वाली हड़तालें रचनात्मक

और कठोर सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को कमजोर करती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत और संतुलित परिणाम हासिल करने की संभावना कम हो जाती है।

समय के साथ, बार–बार हड़ताल बुलाने का प्रयास न केवल अप्रभावी साबित हुआ है बल्कि इसके परिणाम प्रतिकूल भी रहे हैं। बार–बार होने वाली हड़तालों से श्रमिकों में व्यापक थकान दिखाई पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे आह्वान को या तो नजरअंदाज करते हैं या उनमें शामिल नहीं होते हैं। कुछ मामलों में, श्रमिकों के एक छोटे हिस्से को उनकी इच्छा के विपरीत हड़तालों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे इन आंदोलनों की नैतिक वैधता व सामूहिक ताकत और कमजोर हो जाती है। अंततः, यह प्रवृत्ति श्रमिक कल्याण उपायों के समग्र प्रभाव को कम करती है और श्रमिकों के बीच एकजुटता को कमज़ोर करती है।

हड़तालों के व्यापक परिणाम केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहते। औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, दैनिक यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है, और सड़क किनारे के विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों और छोटे सेवा प्रदाताओं की आजीविका बाधित हो जाती है। इन श्रमिकों के लिए, केवल एक दिन की आय का नुकसान भी आजीविका संकट पैदा कर सकता है, उन्हें अपनी सीमित बचत को खत्म करने तथा गंभीर आर्थिक असुरक्षा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है।

भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) को संवाद, आपसी–बातचीत और नियोक्ताओं तथा सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थायी सौदेबाजी और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित एक मॉडल उत्पादन, रोजगार, और समग्र आर्थिक वृद्धि को बाधित किए बिना श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। वर्तमान संदर्भ में, भारतीय केंद्रीय श्रमिक संघों को, जो धीरे–धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं, आत्मविश्लेषण करने और अन्यत्र अपनाई जाने वाली अधिक प्रभावी और दूरदर्शी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

भारतीय श्रमिक को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित किया जाना चाहिए, जो जीवन यापन में आसानी, सामाजिक सुरक्षा और सकारात्मक सहभागिता पर जोर देता हो। विवादों का समाधान टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से करना यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन प्रक्रिया बाधित न हो और राष्ट्रीय विकास की गति सुचारू रूप से जारी रहे। केवल ऐसे संतुलित और व्यावहारिक रणनीतियों के जरिये ही श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में मजबूत और दीर्घावधि में सुरक्षित किया जा सकता है।

कोंकणा सेन शर्मा की साइकोलोजिकल थ्रिलर फिल्म एक्यूज्ड की रिलीज तारीख जारी

ओटीटी पर एक से बढ़कर एक सीरीज उपलब्ध हैं, जिन्हें दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। क्राइम–थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक, ओटीटी पर हर तरह का कंटेंट मौजूद है। अब जल्दी ही डिजिटल दुनिया में एक और शानदार सीरीज जल्दी ही दस्तक देने वाली है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। हम बात कर रहे हैं कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा स्टारर अक्यूज्ड की, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। कोंकणा हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से हैं और एक से बढ़कर एक फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुकी हैं। अब कोंकणा साइकोलॉजिकल थ्रिलर अक्यूज्ड में नजर आएंगी।हाल ही में अक्यूज्ड का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा एकदम अलग ही अंदाज नजर

आईं। पोस्टर के जारी होते ही दर्शकों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गईं। इसी के साथ निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट भी जारी कर दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा– मीरा अपनी सपनों भरी जिंदगी जी रही है। क्या एक राज़ उसकी जिंदगी को बुरे सपने में बदल देगा? कोंकणा सेनशर्मा और प्रतिभा रान्टा अभिनीत फिल्म एक्यूज्ड 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।

बता दें, ये नया साइकोलॉजिकल थ्रिलर 27 फरवरी 2027 को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अक्यूज्ड का फर्स्ट लुक पोस्टर और टीजर जारी किया था, जिसके साथ रिलीज डेट का भी ऐलान किया,

हैरी ब्रूक ने अपने 4,000 टी–20 रन पूरे किए

नईदिल्ली, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी–20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की।

दरअसल, उन्होंने अपने टी–20 क्रिकेट करियर के 4,000 रन पूरे किए। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में 17 रन बनाकर आउट हुए और उनकी टीम को मुकाबले में शिकस्त भी झेलनी पड़ी। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ब्रूक ने अपने टी–20 क्रिकेट करियर में 4,000 रन पूरे किए। क्रिकइंफो के अनुसार, ब्रूक ने 171 मैचों की 158 पारियों में लगभग 34 की औसत से 4,000 रन पूरे किए हैं। इस प्रारूप में 3 शतकों के अलावा, उनके नाम 17 अर्धशतक भी हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) समेत कई टी–20 लीग में खेल चुके हैं।

टी—20 विश्व कप 2026: दासुन शनाका ने श्रीलंका के लिए जड़ा सबसे तेज टी—20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक

नईदिल्ली,श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दासुन शनाका ने टी–20 विश्व कप 2026 के 16वें मुकाबले में ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। ये उनके टी–20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां और टी–20 विश्व कप में पहला ही अर्धशतक रहा। शनाका ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह श्रीलंका के लिए इस प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।

शनाका ने सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और बेहतरीन 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 250 की रही। उन्होंने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर 28 गेंदों में 63 रन जोड़े।

शनाका की शानदार पारी के दम पर ही श्रीलंका ने 225/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। शनाका के अलावा मेंडिस (61) और पवन रत्नायके (60) ने भी अर्धशतक जड़े।शनाका अब टी–20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेला ने साल 2007 के टी–20 विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। श्रीलंका के लिए इससे पहले शनाका ने ही सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 को 18वें दिन लगा जोर का झटका

बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 काफी दिनों से अपना कब्जा जमाकर बैठी है। इसे टक्कर देने के लिए रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 आई, लेकिन उसकी कुर्सी को हिलाने में कामयाब नहीं हुई। वीकेंड पर अच्छी–खासी कमाई करने वाली बॉर्डर 2 को अपनी रिलीज के 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट का मुंह देखना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर मर्दानी 3 का खेल भी खत्म होते दिखाई दिया है।

सैकनिल्क के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने रिलीज के 18वें दिन, यानी सोमवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह कमाई के आंकड़े वीकेंड के मुकाबले बेहद कम हैं, क्योंकि इसने 16वें दिन 5.25 करोड़ और 17वें दिन 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। हालांकि, फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 311.60 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब हो गई है। फिल्म का क्रेज लोगों में बरकरार है जिसकी बदौलत इसने दुनियाभर में लगभग 426 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

उधर यशराज फिल्म्स की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी मर्दानी 3 को तगड़ा झटका लगा है।

जिंदगी न मिलेगी दोबारा 2 के साथ फिर मचेगा धमाल, सीक्वल पर आई ये जानकारी

साल 2011 में रिलीज फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा अपने सीक्वल को लेकर काफी समय से चर्चा में है। फिल्म निर्माता जोया अख्तर एक बार फिर अपनी पसंदीदा तिकड़ी ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल को पर्दे पर वापस लाने की तैयारी कर रही हैं। बताया जाता है कि उन्होंने बहुप्रतीक्षित सीक्वल का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। इस खबर ने फैंस की खुशी को सांतवें आसमान पर पहुंचा गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीक्वल में ऋतिक, फरहान और अभय के किरदार 40 की उम्र में दिखाए जाएंगे। एक सूत्र ने बताया, जोया ने आखिरकार ऐसा ड्राफ्ट तय कर लिया है जिससे वह संतुष्ट हैं। उनका हमेशा से यही कहना था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल तभी बनेगा जब उसमें कुछ नया कहने को होगा। यह पुरानी यादों को ताजा करने वाली फिल्म नहीं है; फिल्म बीते समय और तीनों पुरुषों की जिंदगी में आए बदलावों को दर्शाती है।

आदिल राशिद इंग्लैंड की ओर से 400 टी—20 वाले दूसरे गेंदबाज बने

नईदिल्ली, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्पिनर आदिल राशिद ने टी–20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। 37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टी–20 विश्व कप 2026 के 15वें मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला विकेट लेते ही यह मुकाम हासिल किया। वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज उनका 400वां शिकार बने। वह इंग्लैंड की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने।

राशिद अब क्रिस जॉर्डन के साथ शामिल हो गए। बता दें कि जॉर्डन ने 431 टी–20 मैचों में 27.26 की औसत से 446 विकेट लिए हैं। राशिद ने अपने 358वें मैच (342 पारी) में 400 विकेट का आंकड़ा छूआ। टी–20 क्रिकेट में राशिद 400 विकेट लेने वाले विश्व के

13वें गेंदबाज बने। बता दे कि टी–20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान (699) ने लिए हैं। राशिद ने अपने 4 ओवर के कोटे में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 16 रन दिए। इस बीच उन्होंने 2 विकेट भी लिए।

राशिद ने 2009 में अपने टी–20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक इंग्लैंड की ओर से 139 मैच खेले हैं, इसकी 132 पारियों में लगभग 24 की औसत के साथ 150 से अधिक विकेट लिए हैं। वह किसी भी पारी में 5 विकेट हॉल नहीं ले सके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 4 मैचों में 4 विकेट हॉल लिए हैं।

राशिद टी–20 विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 32 मैच खेले हैं, जिसमें 24.00 की औसत और 6.98 की इकॉनमी रेट के साथ 33 विकेट लिए हैं। उन्होंने टी–20 विश्व कप 2026 में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें 27.50 की औसत और 8.25 की इकॉनमी रेट के साथ 2 विकेट चटकाए हैं।

एक नजर

श्रमिक संगठनों ने पौड़ी में किया प्रदर्शन

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) संबद्ध विभिन्न श्रमिक संगठनों ने कलक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। गुरूवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जमा हुईं। उन्होंने नए श्रम संहिता को तत्काल रद्द करने, भविष्य निधि व बीमा की सुविधा देने, एमडीएम योजना के निजीकरण पर रोक लगाने और न्यूनतम मानदेय 26 हजार करने समेत 10 सूत्रीय मांगें उठाई। यूनियन के संरक्षक टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को कई साल विभागों में बीत चुके हैं, जबकि कई भोजनमाताओं को 15 से 26 साल हो चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से ऐसे श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग उठाई। इस मौके पर यूनियन की जिलाध्यक्ष ऐश्वर्य जुयाल, देवेश्वरी देवी, मुन्नी देवी, विधाता देवी, ज्योति देवी, माया देवी, सुधा देवी, दमयंती देवी, कालिंदी देवी आदि मौजूद रहे।

सीईओ को भेजी विद्यालयों की जांच रिपोर्ट

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : विकासखंड थलीसैंण स्थित श्रीहरि अगस्त्येश्वर प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नौड़ी व नवजागृति बाल विद्या मंदिर लदवाड़ी बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। तीन सदस्यीय समिति ने विद्यालयों की जांच की। बीईओ ने दोनों विद्यालयों की आख्या सीईओ पौड़ी को भेज दी है।

खंड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण विवेक पंवार ने बताया कि तीन सदस्यीय समिति गठित कर दोनों विद्यालयों की जांच करवाई गई। जांच में समिति ने पाया कि संस्कृत विद्यालय दो कक्षाओं में 30 बच्चों के साथ एक किराए के भवन में संचालित हो रहा है। विद्यालय में फर्नीचर, खेलकूद मैदान, स्टाफ रूम, बालिका शौचालय नहीं हैं। जबकि बिजली और पानी की अस्थायी व्यवस्था है। जबकि बाल विद्या मंदिर लदवाड़ी की मान्यता 2017 में ही समाप्त हो गई थी। 24 छात्र संख्या वाला यह विद्यालय तीन कक्षा कक्षों में ही संचालित हो रहा है। समिति ने इस विद्यालय में भी बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली का उल्लंघन पाया। बीईओ पंवार से दोनों विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए पत्रावली सीईओ को भेज दी है।

ग्वेफड़ गांव में मनाया गया जल अर्पण दिवस

रुद्रप्रयाग। विकासखंड अगस्त्यमुनि की ग्राम पंचायत ग्वेफड़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना पूरी होने पर जल अर्पण दिवस मनाया गया। गांव में अब हर नल से नियमित जल आपूर्ति शुरू हो गई है। कार्यक्रम में विधायक भरत सिंह चौधरी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है अन्य गांवों में भी जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 70 लाख की लागत से तैयार की इस योजना को जल संस्थान ने ग्राम पंचायत को सौंप दिया। अब योजना का स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास रहेगा। ग्राम प्रधान लीला सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान महिला मंगल दलों और स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

सीमा पर तैनात रहा भारी पुलिस फोर्स, नहीं पहुंचे संगठन के लोग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुआ विवाद धीरे-धीरे शांत होने लगा था। लेकिन, एक दिन पूर्व ही हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने दीपक के विरोध में कोटद्वार कूच करने की वीडिया सोशल मीडिया में वायरल कर मामले को दोबारा तूल दे दिया। गुरुवार को कौड़िया चैक पोस्ट के साथ ही शहर की अन्य सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। देर शाम तक भी हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी कोटद्वार नहीं पहुंचे।

कोटद्वार के कौड़िया चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस फोर्स

दरअसल, 26 जनवरी को कोटद्वार में एक दुकान का नाम बदलने को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और दीपक कुमार के जिम में घुसने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला। इसके बाद मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगा। करीब एक सप्ताह पूर्व भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कोटद्वार पहुंचकर दीपक को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद कौड़िया चेक पोस्ट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। उस दिन चंद्रशेखर तो नहीं पहुंचे लेकिन, उन्होंने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दीपक तक अपना संदेश पहुंचाया। इसके बाद धीरे-धीरे मामला शांत होने लगा था। लेकिन, एक दिन पूर्व ही ऋषिकेश निवासी हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने दीपक कुमार के विरोध में गुरुवार दोपहर तीन बजे कोटद्वार पहुंचने की चेतावनी दी। इसके बाद विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने भी कोटद्वार आने की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की सीमा पर स्थित कौड़िया चेक पोस्ट के साथ ही अन्य सीमाओं पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर डटे हुए थे। हालांकि, हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जब कोटद्वार के लिए निकल रहे थे तो ऋषिकेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। देर शाम तक पुलिस ने कौड़िया चैक पोस्ट के साथ ही दीपक के जिम के समीप भी डेरा डाला हुआ था।

योग से निरोग रहने का दिया संदेश

आयोजित शिविर में योगाभ्यास करते लोग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : मालिनी वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिवराजपुर मोटाढाक में दस दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अन्य लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया गया। शिविर का शुभारंभ कॉलेज के अध्यक्ष योगंबर सिंह ने किया। कहा कि हमें प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर योगाभ्यास करना चाहिए। इससे हम बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। विद्यार्थियों के बेहतर व स्वस्थ जीवन के लिए योग अति महत्वपूर्ण है। शिविर में विभिन्न आसनों व उनके फायदों के बारे में बताया गया। साथ ही योग से संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की भी अपील की गई। कहा कि योग घर-घर पहुंचे इसके लिए हर व्यक्ति का जागरूक होना अति आवश्यक है। इस मौके पर कुलदीप मैंदोला, डा. रमाकांत कुकरती, सोनम रावत आदि मौजूद रहे।

उच्च न्यायालय के आदेश पर भाजपा ने जताई खुशी

कोटद्वार के झंडाचौक में खुशी व्यक्त करते भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण को न्यायालय की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने पर भाजपा ने खुशी व्यक्त की। कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से मार्ग निर्माण का वादा किया था। सरकार की पुख्ता पैरवी से ही आज मार्ग निर्माण को हरी झंडी मिली है।

गुरुवार शाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी झंडाचौक में एकत्रित हुए। जहां उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि यह एतिहासिक निर्णय है। स्थानीय जनता पिछले कई दशकों से मार्ग निर्माण की मांग उठा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्ग निर्माण को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही थी। न्यायालय में पुख्ता पैरवी से आज सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। कहा कि इस मार्ग निर्माण से कण्वाश्रम का भी बेहतर विकास होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को स्वजरोजगार का भी अवसर मिलेगा। इस मौके पर गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अण्थ्वाल, पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज भाटिया, वीरेंद्र सिंह रावत, कमल नेगी, अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

केन्द्र व्यवस्थापक होंगे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार ने बताया कि जनपद चमोली में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक सम्पन्न कराई जाएंगी। जिलाधिकारी चमोली ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अनुशासन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण कर लिया जाए, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। शासनादेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 (पूर्व की दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21) के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा केन्द्र की सीमाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण तथा परीक्षा संचालन को निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा,

उच्च न्यायालय ने लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण को दी हरी झंडी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : क्षेत्रवासियों की दशकों से चली आ रही लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण की मांग को उच्च न्यायालय ने हरी झंडी दे दी। मार्ग निर्माण पर लगाए गए स्टे को हटाते हुए उच्च न्यायालय ने इसके निर्माण की स्वीकृति दी है। मार्ग निर्माण की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त की है। कहा कि मार्ग निर्माण से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग जिसके निर्माण को लेकर न्यायालय से हरी झंडी मिली है

मालूम हो कि स्थानीय जनता पिछले कई दशकों से मार्ग निर्माण की मांग उठा रही थी। इसके लिए चिल्लरखाल में पिछले कई माह से स्थानीय लोग धरना भी दे रहे थे। यहीं नहीं समय-समय पर शहर में आक्रोश रैली भी निकाली जाती थी।

गुरुवार को उच्च न्यायालय के आदेश से मार्ग निर्माण को अब हरी झंडी मिल गई है। न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने स्वागत किया है। कहा कि प्रदेश सरकार मार्ग निर्माण के लिए तत्पर होकर कार्य कर रही थी। यह मार्ग निर्माण होने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय जनता पिछले लंबे समय से मार्ग निर्माण की मांग उठा रही थी। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में मार्ग निर्माण को लेकर पुख्ता पैरवी की। यही कारण है कि आज उच्च न्यायालय ने मार्ग निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। कहा कि लगभग 11.3 किलोमीटर लंबी इस सड़क से 4.7 किलोमीटर का हिस्सा सेंट्रल फारेस्ट एरिया से होकर गुजरता है, जिसके कारण निर्माण कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन, अब इस मार्ग से 18 गांव के चालीस हजार से अधिक आबादी जुड़ेगी।

बैक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

कोटद्वार के बदरीनाथ मार्ग में मांगों को लेकर धरना देते बैंक कर्मी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : ऑफ इंडिया बैंक इम्लाइज एसोसिएशन के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि लगातार विरोध के बाद भी श्रम कानून में बदलाव किए गए। इससे श्रमिकों के अधिकारों का हनन होगा। इस दौरान पुरानी पेंशन लागू करने की भी मांग उठाई गई। कहा कि कर्मचारियों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गुरुवार को कर्मचारी बदरीनाथ मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक के समीप एकत्रित हुए। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर रही है। केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नए कानून बनाकर श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया है। समस्त श्रमिक सरकार के इस कार्य का विरोध करते हैं। कहा कि सरकार को जल्द से जल्द नियमों में बदलाव कर श्रमिकों के हित में योजना तैयार करनी चाहिए। कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी बैंकों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई है। जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली, बैंकों का विलय न कर बैंकों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए योजना तैयार करने, औद्योगिक घरानों के खराब ऋणों की वसूली के लिए ठोस कानून बनाने, बैंक में ठेका प्रथा को बंद करने, स्थाई नियुक्ति करने व ग्राहकों से अनावश्यक सर्विस चार्ज न वसूलने की मांग उठाई। इस मौके पर यूनियन के प्रांतीय सहायक महामंत्री वीरेंद्र सिंह रावत, जिला सचिव कुलदीप चौधरी, डीपीएस बिष्ट, हरजीत सिंह, रमेश नेगी, भीम प्रसाद आदि मौजूद रहे।

प्रधान संगठन के यशवंत अध्यक्ष और आरती महामंत्री बनीं

नई टिहरी। भिलंगना ब्लॉक प्रधान संगठन की नई कार्यकारिणी का ब्लॉक सभागार में गठन किया गया। राजेंद्र परमार की अध्यक्षता में हुए निर्विरोध चुनाव में यशवंत गुसाईं को प्रधान संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। आरती रतूड़ी को महामंत्री, प्रकाश चंद्र रतूड़ी उपाध्यक्ष, शिवानी भट्ट को महिला उपाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित प्रधान संगठन के अध्यक्ष गुसाईं ने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों के सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।

जनहित के कार्य प्राथमिकता से करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से मिलकर क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान उदय नेगी, सरला देवी, अनिता रावत, मीना चौहान, सुषमा रावत, सुमति सेमवाल, अमित गौड़, गौतम बिष्ट, उत्तम बिष्ट, आशा देवी, विकास बिष्ट, राखी देवी मौजूद थे।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता / मुख्यालय / मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है। धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

Tender No. Date	303-DRM-MB-25-26 dt. 11.02.2026
Name of work	Construction of crew and train manager lobby and Loco office at MB station
Tender Closing Date Time	13.03.2026
Advertised Value (Rs.)	Rs. 1,80,68,669.42/-
Earnest Money (Rs.)	2,40,400.00
Tender Cost (Rs.)	00
Bidding Start Date	27.02.2026
Period of Completion	06 Month

पत्रांक-75-W/2/3/WA/Publication दिनांक-11.02.2026 472/2026

यात्रियों की सेवा में मुस्कान के साथ

सात विद्यार्थियों का एक्सिस बैंक व पेटीएम में कैंपस सलेक्शन

कंपनी में सलेक्शन के लिए इंटरव्यू देते विद्यार्थी

कंपनी के सीनियर एचआर ने लिया साक्षात्कार, छात्रों ने मनाई खुशी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : इंस्टीट्यूट ऑफ हास्पीटेलिटी, मैनेजमेंट एंड साइंसेज (आईएचएमएस) कॉलेज कोटद्वार में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) विषय में, अंतिम वर्ष की शिक्षा ले रहे 07 छात्र-छात्राओं का देश की जानी मानी कंपनी में चयन हुआ है। एक्सिस बैंक और पेटीएम कंपनी में नौकरी मिलने पर छात्रों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है।

बलभद्रपुर बीईएल रोड स्थित आईएचएमएस कॉलेज के कार्यकारी निदेशक अजय राज नेगी ने बताया कि कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट सेलेक्शन के तहत 02 फरवरी को एक्सिस बैंक की एचआर मैनेजर आशु माला और पेटीएम के एचआर मैनेजर रिया और तमन्ना कॉलेज में आए थे।

उन्होंने पहले कॉलेज के सभागार में बीबीए के छात्र-छात्राओं को कंपनी की जानकारी दी और उनसे ऑनलाइन पंजीकरण कराया और इसके बाद साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर छात्र विकांशु तोमर, शिवम सिंह नेगी, रजत दानी, रोहित सिंह रावत, मनदीप रावत, सौरभ रावत, प्रियांशु कंडवाल और अभिषेक रावत को ऑपरेशन एंड सेल्स विभाग में विभिन्न पदों पर दो से तीन लाख के पैकेज का ऑफर लेटर दिए गए।

उन्होंने कहा कि कॉलेज में क्षेत्र के युवाओं की बेहतरीन शिक्षा के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित की गई है। जिसके कारण भारत सरकार की एजेंसी नेशनल एसेसमेंट काउंसिल (नैक) ने उन्हें बी ग्रेड की मान्यता दी है। नेक की रेटिंग मिलने के बाद अब देश की जानी मानी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आईएचएमएस आ रही हैं। कहा कि छात्र-छात्राओं के उज्वल भविष्य के लिए अन्य कंपनियों से भी अनुबंध किए जा रहे हैं।

26 फरवरी तक चलेंगे बैंक शाखावार ऋण शिविर, हर ब्लॉक में होंगे कैंप

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल में बैंक शाखावार ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों सहित ग्रामीणों को अधिक से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सृजित हो सकें। इसके लिए सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे तैयार रोस्टर के अनुसार शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल सुविधा प्रदान करवाना सुनिश्चित करें। जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक जनपद के सभी 15 विकासखण्डों में बैंक शाखा स्तर पर ऋण शिविर आयोजित होंगे। इसमें जिला सहकारी बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों की शाखाएं शामिल रहेंगी। शिविरों में संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक और ब्लॉक विकास अधिकारी की उपस्थिति में पात्र लाभार्थियों के ऋण प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकार के वित्तीय साक्षरता शिविरों से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पाबौ गढ़वाल

पत्रांक 1710/2-लेखा/रा0वि0-निविदा/2025-26 दिनांक फरवरी 12, 2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

उत्तराखण्ड के मा0 राज्यपाल महोदय की ओर से प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकास खण्ड पाबौ के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष 2025-26 में राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत सोलर लाईट आपूर्तिकर्ता फर्मों से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार शीलबन्द निविदायें दिनांक 12.02.2026 से 25.02.2026 तक प्रत्येक कार्यदिवस पर अप्रहान्ह 02:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। निविदा पपत्रों का क्रय विकास खण्ड मुख्यालय पर दिनांक 13.02.2026 से दिनांक 23.02.2026 तक अपराहन 02:00 बजे तक बिक्री किये जायेगे। निविदा विकास खण्ड मुख्यालय पर दिनांक 26.02.2026 को प्रातः 11.00 बजे से उपस्थित आपूर्तिकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति द्वारा खोले जायेगें।

क्र0	मद का	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (ला0 रू0)	धरोहर राशि (ला0 रू0)	निविदा प्रपत्रों का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)			कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैद्यता
						मूल्य	जी0एस0टी0	कुल मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	राज्य वित्त	विकास खण्ड पाबौ के लिए सोलर लाईट।	2025-26	10.00	00.20	1000.00	180.00	1180.00	03 माह	03 माह

नियम व शर्तेः–

1. सोलर लाईट आपूर्ति फर्म का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
2. सोलर लाईट आपूर्ति हेतु ग्राम/स्थान / संख्या हेतु आपको पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
3. निविदा में सोलर लाईट का नाम, मेक मॉडल आदि विस्तृत जानकारी से अवगत कराया जाना आवश्यक है। (सामग्री वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के मानको के अनुरूप होनी आवश्यक है), साथ ही सोलर लाईट के समस्त उपकरण निम्नवत् या उससे उच्चतर के होनी चाहिए।
   1. Solar Street Light 75 wp Pv Solar panel 2. 12 watt-18 watt led luminary light
   3. 12-30 AH Li Battery 4. 5-6m pole
4. सोलर लाईट बताये गये नियत स्थान पर लगाई जानी होगी साथ ही सोलर लाईट को बताये गये स्थान पर पूर्णतः (Transport, Installation) आदि स्थापित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
5. निविदा के साथ पैन/जी0एस0टी0/ बैंक खाता विवरण व फर्म का पंजीकरण संलग्न करना अनिवार्य है।
6. सोलर लाईट की गॉरण्टी / वारण्टी कम से कम पाँच (05) वर्ष की होनी आवश्यक है।
7. बताये गये स्थानों में सोलर लाईट स्थापित करने से पूर्व की जी0पी0एस0 फोटोग्राफ, स्थापित करते हुए की जी0पी0एस0 फोटोग्राफ एवं स्थापित किये जाने के पश्चात के जी0पी0एस0 फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करने होगे तदउपरांत ही भुगतान की कार्यवाही सम्भव होगी।
8. धरोहर (जमानत) के रूप में सोलर लाईट आपूर्तिकर्ता फर्म प्रथम बीजक से 10 प्रतिशत काटी जायेगी। जो एक (01) वर्ष बाद ही अवमुक्त की जायेगी।
9. निविदा की वैद्यता तीन (03) माह तक रहेगी।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में कोटेशन बिना बताये निरस्त करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(हरेन्द्र सिंह कोहली)

संक्षिप्त समाचार

बोर्ड परीक्षा में केंद्र व्यवस्थापक बनेंगे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट

चमोली। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के दौरान केंद्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परीक्षाएं शांतिपूर्वक व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड शासन से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र की सीमाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण, परीक्षाओं को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बताया कि परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, अनुशासन व जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

ग्रामीणों ने की पुरानी बस सेवा बहाल कराने की मांग

चमोली। क्षेत्र की परिवहन सुविधाओं में विस्तार और ग्रामीणों को सस्ता यातायात सुलभ कराने के उद्देश्य से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विश्वनाथ बस सेवा को फिर संचालित कराए जाने की मांग की। उम्मेद सिंह राणा, योगेश कोठारी, मोहन सिंह और क्षेपं सदस्य शंभू प्रसाद सहित अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मांग उठाई है कि जो बस सेवा पूर्व में देहरादून से वाया मयाली–सांकला होकर चलती थी, उसे दोबारा शुरू किया जाए। कहा, इसे सांकला से वाया घनसाली होते हुए देहरादून तक संचालित किया जाए। इस संबंध में विश्वनाथ सेवा के अध्यक्ष कुंवर सिंह ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि क्षेत्रीय जनता की मांग उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित को देखते हुए इस बस सेवा को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया जल्द ही विभाग और पदाधिकारियों के समन्वय से प्रारंभ कर दी जाएगी।

ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को जिला सदस्यों का समर्थन

रुद्रप्रयाग। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में सीटू जिला कमेटी ने बृहस्पतिवार को नगर मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। संगम बाजार से मुख्य बाजार होते हुए रुद्राकांप्लेस तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। वहीं, प्रदर्शन के बाद 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीटू जिला मंत्री कामरेड बीरेंद्र गोस्वामी ने केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। कहा कि बीते साल 21 नवंबर को 29 श्रम कानून समाप्त कर चार नई श्रम संहिताएं लागू करने का निर्णय मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2020 में महामारी के दौरान इन्हें संसद से पारित कराया गया और अब लागू किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि श्रमिक अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। वक्ताओं ने मनरेगा के स्थान पर नई व्यवस्था लाने, राज्यों पर 40 प्रतिशत अंशदान का बोझ डालने व बिजली संशोधन विधेयक 2023 के जरिये निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि इससे आम लोगों पर आर्थिक भार बढ़ेगा।

जिला उद्योग मित्र प्राधिकृत समिति की बैठक संपन्न

रुद्रप्रयाग। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को जिला उद्योग मित्र प्राधिकृत समिति की एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक हुई। बैठक में जिले में उद्योग स्थापना, मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण की समस्याओं और लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र महेश प्रकाश ने बताया कि एकल खिड़की प्रणाली के तहत वर्ष 2024–25 तक 29 आवेदन मिले और सभी स्वीकृत किए गए। वर्ष 2025–26 में अब तक 23 आवेदन आए जिन्हें भी मंजूरी दे दी गई है। शुरुआत से अब तक कुल 188 आवेदन प्राप्त हुए और सभी का निस्तारण कर दिया गया है। वर्तमान में कोई आवेदन लंबित नहीं है। उन्होंने बताया कि भटवाड़ीसैंण औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग व गेट निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है जबकि नए टैंक निर्माण का आकलन शासन को भेजा गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अनावश्यक रूप से कार्यालय न बुलाएं : डीएम

डीएम ने बाल विकास अपरियोजना कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने खिर्सू स्थित बाल विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार हेतु निर्देश दिए कि सभी सुपरवाइजर स्वयं फील्ड में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यों का निरीक्षण करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अनावश्यक रूप से कार्यालय न बुलाया जाए। विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन समय के दौरान उन्हें केंद्र छोड़कर कार्यालय बुलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निरीक्षण के दौरान जनवरी माह के टेक होम राशन (टीएचआर) का वितरण न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण कार्यों का समुचित दस्तावेजीकरण प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देशित किया कि टीएचआर का मास्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से कार्यालय में सुरक्षित और अपडेट रखा जाए। साथ ही, राशन की मांग समय से भेजने और उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि वितरण प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। कार्यालय में उपस्थिति पंजिका की जांच के दौरान केवल एक सुपरवाइजर उपस्थित मिलने और टूर प्लान प्रस्तुत न कर पाने पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सीडीपीओ रीना बिन्दोला को निर्देशित किया कि माह शुरू होने से पहले ही सभी सुपरवाइजरों का टूर प्रोग्राम (भ्रमण योजना) अनुमोदित करवाया जाए। ग्राम चमराड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकत्री रिशु से संवाद करते हुए जिलाधिकारी ने गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं से नियमित संपर्क करने और उनकी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के अभिलेखों के बेहतर रख-रखाव पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यकत्रियों का दिसंबर माह के बाद का लंबित भुगतान तत्काल समय से किया जाए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, तहसीलदार दीपक भंडारी, सुपरवाइजर उर्मिला बधानी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पेयजल योजनाओं का काम जल्द पूरा करें : आर्य

नई टिहरी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जल संस्थान और जल निगम को लंबित पेयजल योजनाओं का काम जल्द पूरा करने को कहा है। आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्ग पर सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के भी कड़े निर्देश दिए हैं। कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बृहस्पतिवार को डीएम ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोनों विभाग के अधिशासी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने लंबित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में जल संस्थान और निगम के अभियंताओं ने बताया जिले में संचालित कुल 1293 पेयजल योजनाओं में से 82 योजनाएं वर्तमान में लंबित है। लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विभागों की ओर से संचालित सभी योजनाओं का विधिवत सत्यापन करने के निर्देश दिए। कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कमी न रहे और जनता को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित हो। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर डीएम ने कहा कि एकल ग्राम पंपिंग योजनाओं के विलयीकरण के संबंध में ग्राम सभाओं की ओर से प्राप्त होने वाले सुझावों और प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करें।

कला-संगीत की नहीं पहुंची पुस्तक, मूल्यांकन पर संशय

प्रधानाध्यापक ने एससीईआरटी से मांगी पीडीएफ प्रति, शीघ्र कार्रवाई की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : वार्षिक मूल्यांकन गुरुवार (12 फरवरी) को होना था, लेकिन छात्रों के पास परीक्षा की पूर्व संध्या तक भी सम्बन्धित विषय की पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंची थी। पुस्तकों का इंतजार करते-करते साल भर हो गया है। जयहरीखाल ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पाँसी में गुरुवार को 19 छात्र-छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन होना था, लेकिन पुस्तकें नहीं पहुंचने से मूल्यांकन पर संशय बना हुआ है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के गृह जनपद का यह मामला है।

शिक्षा विभाग के उच्च स्तर से परीक्षा की पूर्व संध्या तक निर्देश यह आ रहे हैं कि कला एवं संगीत की चयनित पुस्तक से ही छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन किया जाए, लेकिन पुस्तक का अता पता नहीं। छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक व स्कूल स्टाफ गहरे पसोपेश में है। 19 छात्र-छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 12 फरवरी को 1 बजे होनी थी। यह संकट पौड़ी जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पाँसी, विकास खंड जयहरीखाल का है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत इसी पौड़ी जिले से हैं। इस बाबत, प्रधानाध्यापक राम सिंह रावत ने एससीईआरटी, उत्तराखंड को पत्र प्रेषित कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। भेजे गए पत्र में लिखा है कि कक्षा 6 के कला एवं संगीत विषय की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध न होने से विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रधानाध्यापक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि एससीईआरटी द्वारा 11 फरवरी 2026 को जारी पत्र के माध्यम से कक्षा 6 के कला एवं संगीत विषय की पाठ्य पुस्तक के आधार पर मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।

मंदिर परिसर में किया पौधा रोपण

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अंगणी ग्रामवासी समूह की ओर से पौधा रोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रिखणीखाल ब्लॉक के रिख्वलसारी स्थित देवी मंदिर में नवदंपत्ति ने पौधा रोपण किया।

पौधा रोपण से पूर्व ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पौधा रोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना पौधा रोपण हम धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपने जन्मदिवस, विवाह सहित अन्य शुभ समारोह के मौके पर पौधा रोपण करने की अपील की गई। कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। समूह के सदस्यों ने बताया कि घोटला गांव के आशीष रावत व नुनेरा गांव निवासी किरन की कुछ दिन पूर्व शादी हुई थी। दोनों ने वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने पर पौधा रोपण किया। नवदंपत्ति ने रिख्वलसारी स्थित देवी मंदिर परिसर में पीपल के पौधे का रोपण किया।। इस मौके पर सूर्यप्रकाश भारद्वाज, विनय धस्माना, ग्रामप्रधान निक्की रावत (घोटला), गांधी सिंह चौहान, गोपाल सिंह रावत (मंजुली), कल्याण सिंह, मोहन सिंह, धीरज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

आशा कार्यकत्रियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : उचित मानदेय नहीं मिलने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि कार्यकत्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निराकरण पर ध्यान देना चाहिए।

गुरुवार को उत्तराखंड स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन के बैनर तले आशा कार्यकत्री तहसील परिसर में पहुंची। जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कहा कि आशा कार्यकत्री पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। बावजूद उनकी अनदेखी की जा रही है। मानदेय के नाम पर उन्हें नाममात्र का मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने 29 प्रभावशाली श्रम कानूनों के बदले चार नए श्रम कानूनों को लागू किए जाने का घोर विरोध किया। कहा कि वे श्रमिक कानूनों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगें। उन्होंने प्रदेश सरकार से आंगनबाड़ी कार्यत्रियों का न्यूनतम मानदेय 26 हजार रूपए मासिक किए जाने, भविष्य निधि एवं ईएसआई की सुविधा प्रदान करने की मांग की है, इसके अलावा सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की सुविधा का लाभ व 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करवाए जाने की मांग की है। इस मौके पर मीरा नेगी, रंजना कोटनाला, ज्योति रावत, भागीरथी भंडारी, मंजू नेगी, ललिता देवी, बीना देवी, इंदू देवी, गीता देवी, संगीता कुलाश्री, सरोज जदली, मीनाक्षी, राखी रावत मौजूद रहे।

जनसुनवाई कर मौके पर निस्तारण करने की कार्य संस्कृति विकसित करें

शिविर में 25 शिकायतें दर्ज, 138 लोग हुए लाभान्वित

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : मुख्यमंत्री की ह्यजन-जन की सरकार जन-जन के द्वारह्न मुहिम के तहत गुरूवार को विकासखंड एकेश्वर की न्याय पंचायत धरासू के प्राथमिक विद्यालय में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 138 लोगों को सीधे लाभान्वित किया गया, जिससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। एसडीएम रेखा आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पात्र व्यक्तियों को बिना किसी विलंब के लाभ पहुंचाने की है, अतः योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में ही जनसुनवाई कर मौके पर निस्तारण करने की कार्य संस्कृति विकसित करने को कहा।

उपजिलाधिकारी चौबट्टाखाल रेखा आर्य की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में न्याय पंचायत के विभिन्न गांवों से आए 527 ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। शिविर के दौरान उपजिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। कुल दर्ज 25 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया गया, जबकि शेष जटिल मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए समाधान करने को कहा गया। उपजिलाधिकारी रेखा आर्य ने शिविर में लगाए गए सभी 23 विभागीय स्टॉलों का गहन निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देशित किया कि वे केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण करें और विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी सौरभ हांडा, ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट, सहायक प्रबंधक आशुतोष कौशिक सहित राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एनडीपीएस मामले में वांछित मुख्य सप्लायर को भेजा जेल

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : थाना लक्ष्मणझूला पुलिस एवं एस.टी.एफ. की संयुक्त टीम ने एनडीपीएस मामले में वांछित मुख्य सप्लायर को मोदीनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।

बता दें कि 17 दिसम्बर 2025 को थाना लक्ष्मणझूला पुलिस एवं एस.टी.एफ. की संयुक्त टीम द्वारा लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र अंतर्गत जिंदल बगीचा, 6 नंबर कुटिया के पास से अभियुक्त शंकर गिरी एवं मनीष को गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से 10.70 ग्राम एम.डी.एम.ए. (मिथाइलीन डाइऑक्सी मेथैम्फेटामाइन), जो एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ है, बरामद किया गया। इस संबंध में थाना लक्ष्मणझूला पर अभियुक्तों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान नशा तस्करी की सप्लायर चेन को गहनता से खंगालते हुए साक्ष्यों का संकलन एवं तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसमें अभियुक्त आशीष निवासी मोदीनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की संलिप्तता प्रकाश में आई। साक्ष्यों के आधार पर उसे वांछित घोषित किया गया। पुलिस टीम के सतत एवं अथक प्रयासों के फलस्वरूप गत बुधवार को अभियुक्त आशीष पुत्र प्रमोद कुमार, निवासी गोविन्दपुरी, थाना मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक पंकज कुमार, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी चन्द्रशेखर, आरक्षी विरेंद्र प्रताप आदि शामिल थे।

जल संस्थान के सामने 12.12 करोड़ की वसूली की चुनौती

नई टिहरी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जलकर देयकों की 12 करोड़ रुपये की वसूली करना जल संस्थान के लिए बड़ा लक्ष्य है। इसमें सरकारी विभाग से लेकर जिला मुख्यालय में निवासरत टिहरी बांध विस्थापित और अन्य घरेलू के साथ ही व्यवसायिक उपभोक्ता बकाएदार शामिल हैं। इस बार विलंब शुल्क की छूट नहीं मिलने के कारण लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। बावजूद कनेक्शन विच्छेद की समस्या से बचने के लिए जल संस्थान बकाया बिल जमा कराने के प्रयास में जुटा है। जल संस्थान की नई टिहरी शाखा के सामने पानी के भारी–भरकम 12.12 करोड़ रुपये के बकाया बिलों की वसूली करना बड़ी चुनौती है। वर्ष 2024–25 की तरह इस बार अभी तक पुराने बिलों के विलंब शुल्क की शतप्रतिशत छूट नहीं मिलने के कारण उपभोक्ता भी असमंजस में है। बकायेदारों में सबसे अधिक घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ता हैं। उन पर 5.61 करोड़ का बकाया है। जबकि नई टिहरी में टिहरी बांध विस्थापित भी 3.53 करोड़ के बकायेदार हैं। सरकारी विभाग भी 2.97 करोड़ रुपये के बकाएदार हैं। जल संस्थान समय–समय पर विलंब शुल्क में छूट देता है लेकिन इस बार अभी तक छूट संबंधी को दिशा–निर्देश नहीं मिलने के कारण विलंब शुल्क के साथ देयकों का शतप्रतिशत भुगतान करने में भी घरेलु उपभोक्ताओं के पसीने छूटने वाले हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनकर तैयार, सेवाओं के लिए 31 मार्च तक का इंतजार

नई टिहरी। जौनपुर ब्लॉक के श्रीकोट क्षेत्र के लोगों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केंद्र) की सेवाएं शुरू होने के लिए अब 31 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। निर्माणाधीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने भवन को हैंडओवर लेने का काम शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले दिसंबर से केंद्र का संचालन करने की बात कही थी लेकिन पानी और बिजली का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया तय समय पर कार्य पूरा न होने से लोकार्पण की तिथि भी पीछे खिसकती जा रही है। श्रीकोट में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वर्ष 2020 में सरकार ने केंद्र के लिए 42.47 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी लेकिन भूमि के अभाव में यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था। गत वर्ष श्रीकोट गांव निवासी रणवीर सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य विभाग को अपनी दो नाली भूमि दान देकर इस कार्य को गति दी थी।

बहुउद्देशीय शिविर में 380 लाभार्थियों ने लिया योजनाओं का लाभ

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण की तहसील आदिबद्री के न्याय पंचायत देवलकोट (कंसुआ) में गुरुवार को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया। शिविर के दौरान 20 शिकायतें प्राप्त हुईं, सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों के माध्यम से कुल 380 लोगों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाया। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व, कृषि, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, पशुपालन, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, रीप एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। अपर सचिव उत्तराखंड शासन विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि ऐसे शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों ने शिविरों में अपनी समस्याओं के समाधान पर संतोष जताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन जारी रखने की अपेक्षा व्यक्त की। इस मौके पर राज्यमंत्री आरपी सती, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

प्रशासन औद्योगिक विकास हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध

डीएम ने खिर्सू में किसान दिवस पर सुनीं जनसमस्याएं, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने जोर

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : विकासखंड खिर्सू के सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में ह्यकिसान दिवसह्न का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा कृषकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने स्वयं ग्रामीणों और कृषकों से सीधा संवाद कर उनका फीडबैक लिया और कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। डीएम ने कहा कि जो मांगें तत्काल पूरी होने योग्य हैं, उन्हें अविलंब प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

कार्यक्रम में सोलर फेंसिंग, नवाचारी उपकरणों के माध्यम से जंगली जानवरों को भगाने तथा स्वरोजगार और स्थानीय युवाओं हेतु रोजगार सृजन के सुझाव दिए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि व्यावसायिक उत्पादन की जानकारी लेकर इसे जिला योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही सामूहिक घेरबाड़ को प्रोत्साहित करने के लिए इसे भी जिला योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि जंगली जानवरों का आतंक कम हो। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन औद्योगिक विकास हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को सुझाव दिया कि यदि संबंधित ग्रामसभा अपनी भौगोलिक उपयुक्तता और संसाधनों के अनुसार किसी विशिष्ट उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से भेजती है, तो प्रशासन उस पर संज्ञान लेते हुए उद्योग स्थापित करवाने की दिशा में हर संभव कार्यवाही करेगा। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, तहसीलदार दीपक भंडारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय कृषक उपस्थित रहे।

डीएम ने नर्सरी, फॉरेस्ट नर्सरी और बासा होमस्टे का किया निरीक्षण

किसान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी ने वन विभाग की नर्सरी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरी में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को डिस्प्ले (प्रदर्शित) करने के निर्देश दिए, ताकि आगंतुकों को जानकारी मिल सके। नर्सरी परिसर में जर्जर भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया, ताकि हॉर्टी-टूरिज्म का विकास हो सके। क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने ह्यबासाह्न होमस्टे का निरीक्षण भी किया। उन्होंने होमस्टे तक सुगम पहुंच मार्ग (रास्ते) का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उपजिलाधिकारी को संयुक्त निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि होमस्टे की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com